

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 28/14

तारीख रजू- 27/11/2014

कसाना पत्नी सलीम 2- सलीम पुत्र मुमताज  
बतियान गददी मुसलमान निवासीयान भारजा गददी तहसील मलारनाडूंगर।

---प्रार्थीगण

बनाम

मनरूद पुत्र हुसैन खां जाति गददी मुसलमान निवासीयान भारजा गददी तहसील मलारनाडूंगर।  
सरपंच ग्राम पंचायत शेषा, पंचायत समिति बौली तहसील मलारनाडूंगर।  
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत शेषा पंचायत समिति बोली तहसील मलारनाडूंगर।

---अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक- 27/08/15

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत शेषा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा संख्या 04  
05/08/10 पट्टा विलेख पत्रावली संख्या 02 वर्ष 2010 ग्राम शेषा में 200/-रु० पट्टा शुल्क  
55X 60 फिट यानी 3300 वर्गफुट (366.6 वर्गगज)का जारी किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की है  
जारी किये उक्त पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई।  
संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के उपस्थित  
होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त  
पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम  
में ने पट्टा मिलीभगत से तैयार किया है। कोई सार्वजनिक नोटिस चस्पा नहीं किया। नोटिस पर  
दगी फर्जी तैयार की है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि मोका निरीक्षण में  
से कब्जे के बारे में पूछताछ नहीं की है। मोके पर क्या निर्माण है मोका रिपोर्ट में कोई विवरण नहीं  
पंचायत ने मिलीभगत से 25-30 साल पुराना कब्जा होना बता दिया। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस  
में भी तर्क दिया कि यदि पट्टाधारी का निवास होता तो नल बिजली के कनेक्शन होने चाहिये थे।  
नीकार का पति स्वभाव से भोला है अतः उसकी पत्नी ने निगरानी पेश की है। विद्वान वकील  
गण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण मकान पर ताला लगाकर इन्दोर चले गये थे इस  
पट्टाधारी को मकान पर कब्जा करने का मोका मिल गया। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में यह  
तर्क दिया कि जब प्रार्थीगण इन्दोर से भारजागददी गांव आये तो उन्हें आवास पर किसी दूसरे का ताला  
हुआ मिला व प्रार्थीगण ने पट्टाधारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी थी जिसमें पुलिस ने पट्टा  
होना मानते हुए प्रार्थीगण का मकान मानते हुए पट्टाधारी के विरुद्ध चालान पेश किया है। अतः  
गण की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने बहस में तर्क  
दिया कि अप्रार्थी को पट्टा सही जारी हुआ है। पंचायत ने वार्ड पंचो से मोका दिखाया है। सार्वजनिक  
में जारी किये है। अन्य गवाहों की साक्ष्य ली है। वर्तमान सरपंच की तस्दीक पेश की है जिससे  
नीकार का निवास गांव में ही नहीं होना साबित है। मकान का फोटो पेश किया है जिससे भी  
धारी का कब्जा होना साबित है। निगरानीकार की पुलिस एफ.आई.आर. के आधार पर चालान पेश  
जाने से भी पट्टाधारी का कब्जा होना साबित है। पट्टा क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया है अतः रजिस्टर्ड  
वजह को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। निगरानी के द्वारा पट्टा निरस्त नहीं

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

निगरानी संख्या 28/14 रूकसाना/अमरूद वगै०

जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज फरमाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा यथावत रखा जावे। दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस को गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारी का कब्जा 25-30 वर्ष पुराना होना माना है लेकिन कोई दस्तावेजी नल बिजली के बिल या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। पुलिस ने एफ.आई.आर. में जो बयान है उनमें गवाहान ने निगरानीकार का मकान होना बताया है। निगरानीकार की झोपडी रही है। कुछ ने अपने बयानों में निगरानीकार के पति द्वारा पचास हजार रुपये में अमरूद को मकान व जमीन बताया है। चालीस हजार रुपये दे दिये लेकिन दस हजार रुपये का भुगतान नहीं किये जाने से होना बताया है। पट्टाधारी के अधिवक्ता का यह तर्क कि पट्टा रजिस्टर्ड होने से निगरानी के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है यह तर्क उचित नहीं है। यदि मूल आदेश विधि विपरीत है तो उसके पर की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होती है। पट्टा रजिस्टर्ड हो जाने से निगरानी का आधार नहीं होता है। निगरानी में पट्टा जारी करने के बारे में विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। के द्वारा पूछताछ में जो तथ्य आये हैं वे विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली का भी विवरण एक दिन में तैयार किया जाना साबित होता है क्योंकि दिनांक 18/05/10, 05/10, 07/06/10, 20/07/10, 05/08/10 की कार्यवाही का विवरण कम्प्यूटर से प्रिन्टेड है। जाहिर है कि सभी दिनों की प्रोसिडिंग एक साथ लिखी गई है। इससे पट्टा जारी करने का निश्चय पत्र प्राप्त करने के समय ही लिया जाना जाहिर है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के लिए प्रक्रिया चलान उचित रीति से नहीं किया है। तथ्यों के बारे में स्वतन्त्र गवाहों से जाँच नहीं की है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उचित प्रक्रिया से जारी नहीं करने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत शेषा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 05/08/10 निरस्त किया है।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर